बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

○ वर्ष: 23 ○ अंक: 195 ○ नई दिल्ली ○ सोमवार 04 अगस्त 2025 ○ प्रभात कालीन ○ मूल्य: 3 रूपया ○ पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

मुख्य चुनाव आयुक्त पर भड़के सौरभ भारद्वाज, कहा- हर जगह सरकार का ढोल बजा रहे

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ये बयान उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस आरोप के बाद दिया, जिसमें तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची से गायब है. इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा की किसी सेल की तरह काम कर रहा है. सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की किसी इकाई के अध्यक्ष हों. ऐसा लगता है कि सरकार किसी बाबू को रिटायरमेंट के बाद ईनाम के तौर पर चुनाव आयुक्त बना रही है.

तेजस्वी यादव दो मतदाता पहचान पत्र रखकर अपराध किया, भाजपा बोली- इसी लिए एसआईआर का हो रहा विरोध

नई दिल्ली ।

बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के मामले पर खूब हंगामा जारी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने तेजस्वी यादव के पास दो एपिक नंबर होने का दावा किया है और पूछा कि क्या तेजस्वी यादव के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि राजद नेता ने दो मतदाता पहचान पत्र रखकर अपराध किया है।

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई पूरी कहानी

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजद नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1 अगस्त को बिहार में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची जारी की, उसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। तो क्या मैं इस बार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा उस समय तेजस्वी यादव ने अपने मोबाइल को दिखाते हुए EPIC नंबर बताया। तेजस्वी यादव ने जो EPIC नंबर दिया, वो है RAV2916120। यह नंबर तेजस्वी यादव ने मोबाइल पर भी डालकर दिखाया और दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ रहा है। संबित पात्रा ने आगे कहा उसके बाद चुनाव आयोग और पटना के डीएम ने पूरी सचाई को जस का तस रख दिया और कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम मतदाता

सूची में है और कटा नहीं है। उन्होंने बताया कि दीघा विधानसभा में तेजस्वी यादव का नाम पंजीकृत है और वर्तमान में पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी और क्रम संख्या 416 में है। मगर उसके बाद जो बताया गया, वह चौंकाने वाला है। बताया गया कि EPIC नंबर डालकर जो जानकारी सामने आती है, वही जानकारी तेजस्वी यादव ने अपने 2016 के अपने नामांकन के हलफनामे में दाखिल की थी और उसी EPIC नंबर के आधार पर 2020 का चुनाव भी लड़ा था और वह नंबर है RAB0456228। तो ये दो एपिक नंबर कैसे हो गए, एक तेजस्वी यादव ने अपने मोबाइल से बताया और एक चुनाव आयोग ने बताया। अब बताइए ये दो-दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं भाजपा ने पूछा, तेजस्वी यादव के पास दो एपिक नंबर थे तो क्या उनके पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं सर्वोच नेता के पास 2 EPIC नंबर हैं, तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा क्या इसीलिए वे एसआईआर से डरते हैं कांग्रेस और राजद के नेता और उनके कार्यकर्ता, जो बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी के दम पर जीतने के आदी थे, उनका पूरा खेल उजागर हो गया है।

संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद चुनाव आयोग पर तीखा हमला कर रहे हैं, वह भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के बारे में मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव ने दो जगहों पर वोट डाला। तो सोचिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे होंगे। इसीलिए वो इतने घबराए हुए हैं। क्या तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान गलत हलफनामा दाखिल किया था क्या उन्होंने शपथ लेकर झूठ बोला था कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत का पर्दाफाश करने के लिए उनके पास परमाणु बम होने का दावा पाकिस्तान द्वारा भारत को परमाणु धमकी देने जैसा ही एक बेकार दावा है। भाजपा नेता ने कहा कि गांधी और यादव की हताशा संवैधानिक संस्थाओं या देश को बचाने की नहीं, बल्कि अपने परिवारों को बचाने की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव जैसे सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चे राजनीति में स्थापित हो जाएं। पात्रा ने दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए जाने की एक भी शिकायत राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों से नहीं आई है।

7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, इन-इन मुद्दों पर मंथन करेगा विपक्ष

नई दिल्ली । बिहार चुनाव और एसआईआर जैसे मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने के लिए जहां संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहा है. वहीं अब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को खाने पर बुलाया है.सात अगस्त को यह बैठक होगी और आठ अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेता संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च भी करेंगे. इस बैठक के एजेंडा में उप राष्ट्रपति का चुनाव भी शामिल है. जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जहां एनडीए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार ढूंढ रही है वहीं इंडिया गठबंधन भी एक सशक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहा है.

उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष बनाना चाहता है रोचक

इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने एनडीटीवी को बताया है कि विपक्ष इस बार ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जिससे की उपराष्ट्रपति का चुनाव रोचक हो जाए. विपक्ष को लगता है कि इस बार का लोकसभा और राज्यसभा का गणित ऐसा है कि यदि कोई दमदार उम्मीदवार

उपराष्ट्रपति के लिए उतारा जाए तो मुकाबला पिछली बार की तरह एकतरफा नहीं रहेगा. सबसे बड़ा सवाल है कि यदि विपक्ष बिहार या आंध्र प्रदेश से कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए देता है तो नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू क्या करेंगे.

जगदीप धनखड़ के खिलाफ मार्गरिट अल्वा को बनाया गया था उम्मीदवार

पिछली बार जगदीप धनखड़ और माग्रेट अल्वा के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें धनखड़ को 528 वोट मिले थे और अल्वा को 182, मगर इस बार हालात अलग हैं. एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है और इस एकजुटता का परिचय उपराष्ट्रपति के चुनाव में देना चाहता है. एसआईआर के नाम पर कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस और डीएमके भी साथ है क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में उनके राज्यों में भी एसआईआर करवाया जाएगा.

लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं वोटिंग

उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं जिसमें राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसद भी भाग लेते हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख़ की घोषणा हो चुकी है और 9 सितंबर को वोटिंग होगी.जिसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 233 और 12 मनोनीत सांसद भाग लेंगे.सात अगस्त की बैठक में इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करेगा. जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अगले पांच साल तक इस पद पर बने रहेंगे. धनखड़ का कार्यकाल अभी दो साल बाकी था मगर जिस ढंग से उनकी विदाई हुई है ऐसा माना जा रहा है बीजेपी इस बार अपने किसी खास नेता को उम्मीदवार बनाएगी जो राज्य सभा का संचालन ठीक से कर सके. इसी तरह कांग्रेस भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को एक शक्ति प्रदर्शन से कम के रूप में नहीं देख रही है इसलिए इस बार का उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है.

महिला आर्थिक शोषण के कारण मुआवजा पाने की हकदार, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

नई दिल्ली। भरण पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यातनाओं की सही तारीख और समय न बता पाने का मतलब यह नहीं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर उसका मामला बेबुनियाद है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने उसे और उसके नाबालिग बच्चे को चार हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। आरोप लगाया था कि पर्याप्त दहेज मिलने के बावजूद, पति ने उसके परिवार से मोटरसाइकिल की मांग की और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपनी ननद की शादी के लिए 50 हजार रुपये लाने के लिए भी कहा गया और जब वह यह मांग पूरी नहीं कर पाई, तो उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया। याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि पति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पत्नी ने उसका साथ क्यों छोड़ा और उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई याचिका भी दायर नहीं की। अदालत ने कहा यह अहम तथ्य है कि याचिकाकर्ता महिला के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता शारीरिक क्रूरता/उत्पीड़न की सही तारीख और तरीका बताने में विफल रही। हालांकि, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता यातनाओं की सही तारीख और समय बताने में विफल रही। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता का मामला निराधार है। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीएडब्ल्यू शिकायत दर्ज कराई थी और इसलिए, उसके मामले को निराधार नहीं कहा जा सकता। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि महिला आर्थिक शोषण के कारण मुआवजा पाने की हकदार है। अदालत ने पत्नी और नाबालिग बच्चे को चार हजार रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया।

दिल्ली में युवती ने सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में लगाई छलांग, जब तक बचाव टीम पहुंची हो चुकी थी मौत

नई दिल्ली । उत्तरी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से शनिवार सुबह एक युवती ने अपना बैग पुल पर रखकर यमुना में छलांग लगा दी। लोगों ने युवती को कूदते हुए देखा तो फौरन मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल विभाग के अलावा गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम जब तक पहुंची तब तक वह डूब चुकी थी। गोताखोरों ने उसको कुछ ही देर बाद यमुना से निकाल लिया। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बैग से मिले फोन नंबर की मदद से मृतका की शिनाख्त छाया (23) के रूप में हुई है। पुलिस को मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना के बाद शाम के समय युवती के परिजन तिमारपुर थाने पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद आशंका व्यक्त की जा रही है कि पारिवारिक कलह की वजह से युवती ने यह कदम उठाया। परिजनों और पति से पूछताछ की जा रही है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11.15 बजे उनकी टीम को एक युवती के यमुना में कूदने की सूचना मिली। तिमारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में युवती की पहचान न्यू सीलमपुर, गुरुद्वारे वाली गली निवासी छाया के रूप में हुई। छाया यहां अपने परिवार के साथ रहती थी।करीब दो साल पहले छाया ने चरणजीत उर्फ नितिन नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। अब उसने ऐसा कदम क्या उठाया, इसकी पड़ताल की जा रही है। चरणजीत रैपिडो चालक है। पुलिस ने उसके पति को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।

पीएम मोदी की स्वदेशी अपील को व्यापारियों से मिला जोरदार समर्थन, मैदान में उतरे 48000 व्यापारी संगठन

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से भारतीय सामान खरीदो और बेचो की अपील को बड़ा समर्थन देते हुए कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रविवार को घोषणा की है कि बाबत 10 अगस्त से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना है। यह निर्णय आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में लिया गया, जिसमें देश के 26 रायों से आए 150 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री तथा दिल्ली चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया की सभी व्यापारी नेताओं ने एक स्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को भारत की अस्मिता का प्रतीक बताते हुए इस अभियान का नाम भारतीय सामान ङ्क हमारा स्वाभिमान रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त करती है। विदेशी कंपनियों की एकाधिकारवादी नीतियों से बचकर यदि हम अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा दें, तो न केवल हमारा व्यापार मजबूत होगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार भी सशक्त होंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने अभियान के बारे में बताते हुए कहा की देश भर में फैले 48,000 से अधिक व्यापारी संघटनों की भागीदारी के साथ यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा।हर राय व ज़िले में व्यापारी, उपभोक्ता व नागरिक समाज के साथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया, पोस्टर, रैलियों व जन संवाद के माध्यम से लोगों को भारतीय उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, व्यापार मंडल, एनजीओ और समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाएगा।

खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करने के कारणों के बारे में कहा कि विदेशी कंपनियों की अनुचित व्यापार नीतियों से छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं जिससे भारत के स्थानीय व्यापार को बड़ा नुकसान हो रहा है । उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता आज विश्वस्तरीय है, और कीमत भी उचित है। भारतीय उत्पादों की खरीद से स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और व्यापारियों को समर्थन मिलेगा।

विदेशी वस्तुओं की अंधाधुंध खपत से भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है, जिसको रोकना जरूरी है। इससे भारतीय संस्कृति, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

कैट ने सभी व्यापारियों से आह्वान किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर केवल भारतीय सामान उपलब्ध है जैसे पोस्टर लगाएं और ग्राहकों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित करें। यह अभियान भारत के आर्थिक स्वाभिमान की नींव को और मज़बूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

राजनीति और मित्रता-आदर्श या अवसरवाद -अच्छे मित्र का साथ हो तो, बढ़ी से बढ़ी चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है

वैश्विक स्तरपर आज विभिन्न देशों के बीच कटुता बढ़ती जा रही है। विभिन्न समुदायों के बीच नफ़रत का दायरा बढ़ता जा रहा है। आंदोलनों का जाल अनेकों देश में घटित समस्याओं के चलते बढ़ता जा रहा है जो हम भारत- पाकिस्तान, रूस-यूक्रेन, इसराइल -हमास कंबोडिया- थाईलैंड, अमेरिका-ईरान,चीन- ताइवान व अन्य देशों के बीच सहित अनेको देशों में देख रहे हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इन सब समस्याओं को पाटनें का सबसे सरल सस्ता सटीक उपाय है,मित्रता! दोस्ती, अपनापन, यदि इस सटीक अस्त्र का उपयोग दुनियां के सभी देश करें तो यूक्रेन-रूस, हमास- इजरायल ईरान- इजरायल के बीच युद्ध व विभिन्न अंतरराष्ट्रीय यूनियनों के बीच कटुता कभी नहीं बढ़ेगी। विश्व के चारों ओर शांति रूपी स्नेह की बारिश होगी तो, खुशहाली को आना ही पड़ेगा। जिसपर हर देश का नागरिक खुशहाल जीवन का लुफ्त उठाएंगे। इसलिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 अप्रैल 2011 को अपने 65 वें सेशन में एजेंडा आइटम नंबर 15 कल्चर ऑफ पीस के अंतर्गत 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जबकि भारत अमेरिका बांग्लादेश सहित अनेकों देश अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले रविवार को मनाते आ रहे हैं जो इस वर्ष 2025 के अगस्त का पहला रविवार 3 अगस्त 2025 आया है। वर्तमान परिपेक्ष में अगर मित्रता का वैश्विक परिपेक्ष लेकर, दुनियां के पूरे देशों और नागरिकों द्वारा वर्ष 2025 में अपनाया जाती है तो मेरा मानना है कि आपसी युद्ध की नौबत कभी नहीं आएगी। चूंकि अच्छे मित्र का साथ हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों सेआसानी से निपटा जा सकता है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,राजनीति और मित्रता - आदर्श या अवसरवाद-अच्छे मित्र का साथ हो तो,बढ़ी से बढ़ी चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। साथियों बात अगर हम मित्र के महत्व को समझने की करें तो, कोई व्यक्ति जन्म के बाद खुद से अपने बल पर जो पहला रिश्ता बनाता है, उसे दोस्ती कहते हैं। परिवार से बाहर एक दोस्त ही हमारा मार्गदर्शक,सलाहकार, राजदार और शुभचिंतक होता है। इसी दोस्ती के नाम एक खास दिन समर्पित किया गया है,जिसे फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि दुनियां भर में साल में दो बार दोस्ती दिवस मनाते हैं। ऐसे में कई लोग असमंजस में हैं कि असली मित्रता दिवस किस दिन मनाएं। आमतौर पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि भारत में हर साल अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है, इस दिन हर कोई अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है, इस साल भारत में 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है।व्यक्ति के जीवन में दोस्त जरूर होते हैं। अगर न हों तो एक दोस्त जरूर बनाना चाहिए। दोस्ती कभी भी हो सकती हैं, उसमें उम्र, लिंग या किसी अन्य तरीके का कोई भेद नहीं होता। दोस्त आपका ऐसा समर्थक होता है जो हमारी तरक्की के लिए अच्छी सलाह देता है और हमारी खुशी में खुश होता है। ऐसे में हमारे जीवन को सरल, सुलझा हुआ और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए दोस्ती दिवस मनाते हैं और इस मौके पर दोस्त को खास महसूस कराते हैं।दोस्ती जीवन के सबसे अनमोल बंधनों में से एक है।यह रिश्ता खून का न होते हुए भी बढ़-चढ़कर साथ निभाता है।सात अक्षरों का शब्द फ्रैंड्स बेशक बहुत सरल हो, लेकिन जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो दोस्त हमारे साथ होते हैं। वैसे तो दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है,फिर भी इस दिन को और खास बनाने के लिए हर साल फ्रेंडशिप-डे मनाया जाता है।यह दिन दोस्तों के महत्व और हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी सम्मान और मान्यता देता है। यह दिन प्रशंसा व्यक्त करने, रिश्तों को मजबूत करने और दोस्ती से मिलने वाली खुशी का जश्न मनाने का अवसर है। इस दिन,लोग आम तौर पर उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं, संदेश भेजते हैं और एक साथ समय बिताते हैं, ये सभी मजबूत और सहायक दोस्ती के महत्व को मजबूत करने में मदद करते हैं। जबकि विशिष्ट तिथि देश के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, मूल विचार एक ही रहता है, यानी हमारे जीवन को समृद्ध करने वाले रिश्तों का जश्न मनाना और उन्हें संजोने को रेखांकित करना जरूरी है। साथिया बातें अगर हम 3 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के परिपेक्ष में राजनीति और मित्रता एक आदर्श या अवसरवाद के रूप में देखे तो,भारत और अमेरिका की दोस्ती को राजनीति और अवसरवाद दोनों के नजरिए से देखा जा सकता है। जिसका सटीक उदाहरण ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ जो 1 अगस्त 2025 से लागू था उसको 7 अगस्त तक एक्सटेंशन कर दिए हैं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह एक रणनीतिक साझेदारी है जो दोनों देशों के हितों को साधने का काम करती है,जबकि अन्य इसे अवसरवादी संबंधों के रूप में देखते हैं, जहां दोनों देश अपने-अपने फायदे के लिए एक-दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। जो रेखांकित करने वाली बात है साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस को मनाने के विचार व उद्देश्यों की करें तो, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा,संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की गई थी कि लोगों, देशों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के बीच सेतु का निर्माण कर सकती है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों, देशों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच मैत्री को संजोना था, जो शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकें और समुदायों के बीच सेतु का निर्माण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाने के लिए,संयुक्त राष्ट्र सरकारों राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य सामाजिक समूहों को मित्रता और इसके महत्व के बारे में लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम,प्रतियोगिताएं और अन्यगतिविधियां आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा विश्व अनेक चुनौतियों, संकटों और विभाजनकारी शक्तियों का सामना कर रहा है,जैसे गरीबी, हिंसा, मानवाधिकारों का हनन,तथा अन्य अनेक जो विश्व के लोगों के बीच शांति, सुरक्षा, विकास और सामाजिक सद्भाव को कमजोर करते हैं।उन संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए, मानव एकजुटता की साझा भावना को बढ़ावा देने और उसका बचाव करके उनके मूल कारणों का समाधान किया जाना चाहिए, जिसके कई रूप हैं, जिनमें से सबसे सरल है मित्रता।मित्रता के माध्यम से,सौहार्दपूर्ण संबंधों को संचित करके और विश्वास के मजबूत संबंध विकसित करके,हम उन मूलभूत बदलावों में योगदान दे सकते हैं जो स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के लिए तत्काल आवश्यक हैं, एक सुरक्षा जाल बुन सकते हैं जो हम सभी की रक्षा करेगा, और एक बेहतर विश्व के लिए जुनून पैदा करेगा जहां सभी लोग व्यापक भलाई के लिए सटीकता से एकजुट होंगे। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस की पृष्ठभूमि की करें तो,प्रस्ताव में युवा लोगों को भावी नेताओं के रूप में सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां शामिल हों और अंतर्राष्ट्रीय समझ और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिले।अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों को ऐसे आयोजन, गतिविधियां और पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सभ्यताओं के बीच संवाद, एकजुटता, आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ावा देने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में योगदान दें।

अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस एक पहल है जो यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति को मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के एक समूह के रूप में परिभाषित करने के प्रस्ताव पर आधारित है जो हिंसा को अस्वीकार करते हैं और समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उनके मूल कारणों को संबोधित करके संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं।

इसे 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य, शिक्षा के माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना; सतत आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना;सभी मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना;महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करना;लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना;समझ, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देना;सहभागी संचार और सूचना और ज्ञान के मुक्त प्रवाह का समर्थन करना;अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अत्यंत जरूरी बढ़ावा देना।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट - कुछ सवाल

बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षणके बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। बिहार में कुल 7.24 करोड़ वोटर बचे हैं। आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में ज्यादातर लोग या तो अब जीवित नहीं या वे दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गएहैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया है, जोशुरू से ही विवादों के घेरे में है। क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची का गहन विश्लेषणभी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और इस बात का आंकलन कर रहे हैं कि 65 लाख से अधिक वोट कटने का फायदा और नुक्सान किसे होगा। सबके अपने-अपने विश्लेषण हैं।

एक विश्लेषण यह सामने आया है कि जहां सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं उस इलाके में भाजपा नीत एनडीए ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। जहां सबसे कम वोट कटे हैं वहां राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के गठबंधन का दबदबा रहा है। किसको कितना फायदा और नुक्सान होगा यह तो चुनाव ही बताएंगे लेकिन कुछ सवाल अब भी बरकरार हैं जिनका उत्तर चुनाव आयोग को देना है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उसने चुनाव आयोग को आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। तब चुनाव आयोग ने कोर्ट में हल्फनामा देकर स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड और राशन कार्ड वैध दस्तावेज नहीं हैं और इन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। इस पर विवाद और तीखा हो गया और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है तो वह हस्तक्षेप करेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब किसी बैंक में खाता खुलवाने से लेकर रसोई गैस के पंजीकरण के लिए हर जगह आधार अनिवार्य है तो नागरिकता की प्रमाणिकता के लिए वह वैध दस्तावेज क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। मृत मतदाताओं और पलायन करके दूसरी जगह जा बसे मतदाताओं के नाम हटाया जाना उचित है लेकिन बिहार के अशिक्षित, गरीब और पिछड़े हुए लोगों का क्या होगा जिनके पास जरूरी दस्तावेज ही नहीं हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं जिनमें से कुछ प्रमुख प्रश्नों में मतदाता सूची से हटाए गए ट्रैसलैस (गैर-स्थानीय) लोगों का आधार क्या है, मृत मतदाताओं के नाम किस आधार पर हटाए गए वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में कितने लोगों तक यह सूची पहुंचाई गई, विधानसभा वार कितने नाम हटाए गए समेत अन्य सवाल शामिल हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि यदि इन सवालों का समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो यह चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेगा। बैठक के बाद सभी दलों ने संकेत दिया है कि अगर चुनाव आयोग संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो इस मुद्दे को अब बड़े आंदोलन का रूप भी दिया जा सकता है। महागठबंधन के नेताओं को ठोस साक्ष्य के साथ इस मामले में आगे आना चाहिए।

जिनके नाम कटे हैं, बेशक ऐसे मतदाता 1 सितम्बर तक अपील कर सकते हैं लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर उसकी विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कई बीएलओ इसलिए निलम्बित किए गए क्योंकि वे मनमाने ढंग से फार्म जमा कर रहे थे।

अनेक जगह पाया गया कि वे घर पर नहीं मिलने वाले मतदाताओं के बारे में आसपास से पूछकर ही काम चला रहे थे। इस आधार पर किसी व्यक्ति को पलायन कर चुका माना गया। इस संबंध में परिवार से कोई प्रमाणपत्र नहीं लिया गया। उधर विपक्ष चुनाव आयोग को वोटर चोर करार दे रहा है और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। एक बार फिर किसी का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है तोउसे हटाने के लिए एक तय प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। कानून में यह धारणा आप के पक्ष में है कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आपने जरूरी दस्तावेज पहले ही दिए होंगे। चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सारा बोझ वोटरों पर डाल दिया कि वे खुद साबित करें कि वे भारतीय नागरिक हैं। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी ताकत निष्पक्ष चुनाव और जन भागीदारी में निहित है। चुनाव आयोग हर नागरिक के स्वतंत्र होकर वोट डालने के अधिकार की रक्षा करता है। अगर इसकी कार्य प्रणाली पर ही संदेह होने लगे तो लोकतंत्र के 'लहूलुहान' होने की आशंकाएं बन जाती हैं। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 में चुनाव आयोग को पुनरीक्षण के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाना ही चाहिए। आजकल बंगलादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ कर उन्हें वापिस भेजा जा रहा है। यदि आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज ही फर्जी बनाए जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। चुनाव आयोग को स्पष्ट नियमों के साथ सामने आना होगा। मतदाता पहचान पत्र तो चुनाव आयोग की निगरानी में ही बनते हैं, फिर उन्हें भरोसे का दस्तावेज क्यों नहीं माना जा रहा फिर आयोग की सूची में जिस आवासीय प्रमाणपत्र को जगह दी गई, उसकी हालत यह है कि बिहार के मसौढ़ी से एक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी करने की खबर आई। ऐसे में किस प्रमाणपत्र को सबसे विश्वसनीय माना जाएगा यह सच है कि देश में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया जरूरी है। मगर इस प्रक्रिया की जटिलता से कोई योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर ही है।

घरेलू हिंसा की आड़ में ब्लैकमेलिंग

हमारे यहां महिलाओं को कभी कमजोर और अबला के रूप में जाना जाता था और समय बदलने के साथ ही ऐसा लगता है कि कानून भी महिलाओं के पक्ष में जाने लगे। इस कड़ी में नारी पर कथित भ्रष्टाचार या जुर्म को लेकर या फिर शारीरिक शोषण के मामलों में कानून की बदलती परिभाषाओं ने दोषी लोगों को कठघरे में खड़ा कर सजा भी दिलाई। इससे एक अवधारणा भी बनी कि महिलाओं पर जुर्म करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। यहां हम अब उस घरेलू हिंसा का उल्लेख करना चाहेंगे जो पुरुषों तथा महिलाओं से जुड़ी है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के पक्ष में कानूनी फैसलों ने काफी हद तक यह स्थापित कर दिया कि पुरुष लोग महिलाओं पर जुर्म ढहाते हैं तथा उन्हें वैवाहिक व पारिवारिक जीवन से बेदखल कर डालते हैं। इन मामलों में एक बड़ी बात आज की तारीख में यह भी है कि बेचारे पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं और ट्रेजिडी यह है कि कोई कानून उनके हितों की सुरक्षा के लिए बना ही नहीं है। इस कड़ी में धारा 498ए के दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़रही हैं। उदाहरण के तौर पर उद्योगपति मिस्टर एक्स की पत्नी हर महीने जेब खर्चा एक लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने की मांग को लेकर उन्हें पार्टियों में हर बार बेइज्जत कर चुकी है। एमए पास पत्नी अपने पति को एक प्लाट अपने नाम पर करने की मांग को लेकर दोनों बच्चे लेकर मायके चली गई तथा अब डाइवोर्स की धमकी दे रही है। एक और अफसर की पत्नी अपने मां-बाप, भाई को पति के घर स्थायी तौर पर रखने के लिए मांग कर रही है तथा कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। ये छोटे-छोटे उदाहरण घरेलू हिंसा हैं, जिनमें पति प्रताड़ित है। ऐसे लाखों उदाहरण पत्नी प्रताड़ित पतियों के हैं, उन्हें भी सुरक्षा चाहिए लेकिन कानूनी फैसले इस मामले में बड़े उदाहरण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कई डिबेट्स देखे हैं महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित कर धन मांगने को ब्लैकमेलिंग कहा गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज मामलों में महिलाओं की शिकायत पर पति या ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी दो माह तक न किए जाने की ऐतिहासिक व्यवस्था भी दी है। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं द्वारा धारा 498ए के दुरुपयोग तथा पति या उसके परिवार ब्लैकमेलिंग के केस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों में आईपीसी की धारा 498ए यानी विवाहित महिलाओं के साथ ससुराल में क्रूरता संबंधी अपराध के अन्तर्गत दो महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने दुरुपयोग रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13 जून, 2022 को दिए गए निर्णय में उल्लेखित परिवार कल्याण समिति के गठन व उपायों का समर्थन किया है। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश लागू रहेंगे और अधिकारी उनका पालन करें। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई व न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 22 जुलाई को यह आदेश दिया। आईपीसी की धारा 498ए पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को अपराध मानती है। इस प्रावधान का अक्सर उन मामलों में उल्लेख किया जाता है जहाँ महिलाओं के साथ क्रूरता की जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन मामलों में नहीं किया गया है ।

सम्पादकीय...

एसआईआर फॉर्म में पूछा जाना चाहिए- आपने किसे वोट दिया और किसे देने वाले हैं

संसद की कार्यवाही चल रही है। सभी संसद सदस्यों से ले कर सभी मंत्री तक उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और लें भी क्यों नहीं। आखिर बहस सिंदूर पर जो हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर। इसी ऑपरेशन सिंदूर पर तो सरकार जी अगले कई इलेक्शन लड़ेंगे। कम से कम तब तक तो लड़ेंगे ही जब तक इलेक्शन लायक कोई अन्य मुद्दा नहीं मिल जाता है। अब हम उन्नति कर चुके हैं। कम से कम इस मामले में तो कर ही चुके हैं। अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि चुनावी मुद्दे नहीं हैं। इलेक्शन के नाम पर ध्यान आया, इलेक्शन लोकतंत्र का सबसे बड़ा औजार है। लोकतंत्र होना है तो इलेक्शन होना भी जरूरी है। और इलेक्शन होना है तो उसे जीतना भी है। बाज लोग इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सरकार जी भी उनमें से एक हैं। ठीक है, इलेक्शन जीते हैं तभी तो सरकार जी बने हैं। नहीं जीतते तो कोई और सरकार जी बना होता। तो सरकार जी बनने और बने रहने के लिए इलेक्शन जीतना बहुत ही जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब देखो बिहार में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है या फिर उससे भी आगे की बात हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग जो भी कुछ कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। मतलब सरकार जी के लिए ही कर रहा है। सरकार जी और देश अलग हैं क्या अगर आप इन्हें अलग मानते हैं तो आप देशद्रोही हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है। पर चार सौ सीट आ जातीं तो आ जाता। कोई शक है क्या अब चार सौ सीट नहीं आईं तो उसमें सारी गलती चुनाव आयोग की ही है। इसीलिए चुनाव आयोग को टाइट किया जा रहा है। और टाइट करने से रिजल्ट भी तो मिला है। महाराष्ट्र में ऐसे ही नहीं मिला था उम्मीद से भी अच्छा, मनमुताबिक परिणाम। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, उसी का परिणाम मिला था, और बीजेपी जीती थी। अब चुनाव आयोग बिहार में काम कर रहा है। महाराष्ट्र से उल्टा कर रहा है। नहीं, नहीं, बीजेपी को हराने के लिए नहीं कर रहा है। कर तो बीजेपी को जिताने के लिए ही रहा है पर कर दूसरी तरह से कर रहा है। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा कर किया गया, बिहार में वोट घटा कर किया जा रहा है। अब अगली बार जब भी कहीं भी एसआईआर हो, मतलब वोटर लिस्ट के पुनरनिरीक्षण की जरूरत हो, वोट जोड़ने या काटने की जरूरत हो तो जो फॉर्म भरवाया जाये उसमें एक कालम जरूर रखा जाये। वह यह कि आपने पिछले चुनाव में किसे वोट दिया था और आने वाले चुनाव में किसे वोट देने वाले हैं। जो सरकार जी की पार्टी का नाम लिखे उसे मतदाता लिस्ट में शामिल किया जाये और बाकी को देशद्रोही, विदेशी, या फिर कुछ और घोषित कर लिस्ट से बाहर फेंक दिया जाये। देखें सरकार जी की पार्टी कैसे हारती है और कोई और कैसे जीतता है। देखिए, बात हमने संसद की शुरू की थी और बात करने लगे वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट और संसद में सम्बन्ध है और बहुत गहरा संबंध है। वोट पा कर, चुनाव में जीत कर ही तो संसद में पहुंचते हैं। और वोट वही दे पाता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो। और चुनाव भी वही लड़ पाता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो। तो है ना संसद में पहुंचने और संसद में पहुंचाने में वोटर लिस्ट का महत्व। संसद में पहुंचने से ध्यान आया हमारे सरकार जी जब पहली बार संसद में पहुंचे थे तब संसद की सीढ़ियों पर झुक गए थे। वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर लगाई थी। %संसद माता% को प्रणाम किया था। समझ तो तभी आ जाना चाहिए था कि अब संसद कैसे चलेगी। पर हम समझे नहीं। समझ जाना चाहिए था कि सरकार जी संसद को कितना महत्व देंगें, पर समझे नहीं। अब समझ आया है। जब संसद चलेगी, तब सरकार जी सब काम करेंगे पर संसद में नहीं आएंगे। विदेशी दौरे करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे, योजनाओं का उद्घघाटन करेंगे, परियोजनायें शुरू करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे पर संसद में नहीं आएंगे। आएंगे तो सुनने नहीं, सुनाने आएंगे। बिना प्रश्न सुने, उत्तर देने आएंगे। संसद अब ऐसे चलेगी कि कोई मंत्री अब राज्यसभा में बोलेगा, आसन की परवाह किए बिना बोलेगा, कि रिकॉर्ड में सिर्फ वही जायेगा जो मैं बोलूंगा। लोकसभा में स्पीकर भारतीय, भारतीय के नारे लगा रहे सदस्यों को शोर न मचाने, शांत हो जाने के लिए कहेंगे और मोदी, मोदी का शोर मचा रहे सदस्यों को देख कर मंद मंद मुस्कराएंगे। जी हाँ, अब भारतीय, भारतीय कहना शोर माना जायेगा।

मोदी राज्यसभा में इसलिए नहीं गए

अनिल जैन

चीन के प्रति भारत की विदेश नीति कैसी हो गई है इसे लेकर भाजपा के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह-तरह के आरोपों को अलग भी रख दिया जाए तो यह सच सबको दिख रहा है कि चीन के सामने भारत की विदेश नीति घुटने टेकने वाली है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई के समय चीन ने खुल कर पाकिस्तान का साथ दिया। उसे सेटेलाइट के जरिये भारतीय विमानों की पोजिशन बताई और उन्हें मार गिराने में मदद की। इसके बावजूद भारत के रक्षा और विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में बड़े गर्व के साथ पोस्ट की। भारत की कमजोर विदेश नीति का सबसे बड़ा सबूत चीन के सबसे बड़े बांध पर भारत की चुप्पी है। चीन ने 19 जुलाई को ऐलान किया कि वह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। समझा जा रहा है कि इसके जरिये वह समूचे पूर्वोत्तर की पारिस्थितिकी को नियंत्रित करेगा और जब चाहेगा तब उसे तहस-नहस कर देगा। इस बांध के जरिये वह पानी रोक कर सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है और पानी छोड़ कर बाढ़ से तबाही मचा सकता है। लेकिन भारत इस पर कुछ नहीं कर रहा है। अगर भारत इस तरह का कोई काम कर रहा होता तो चीन क्या करता शायद अब तक प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करता और काम रुकवाने की भरसक कोशिश करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में तो पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जहां वे एक घंटा 40 मिनट बोले और देश के लोगों को कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया। लेकिन राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली में मौजूद रह कर सदन में नहीं आने को सदन का अपमान बताया और उनके नेतृत्व में सभी विपक्षी पार्टियों ने अमित शाह के भाषण के दौरान सदन से वॉकआउट किया। दूसरी ओर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष उन्हीं से नहीं निबट पा रहा है तो प्रधानमंत्री को क्यों बुलाना चाह रहा है। इससे उन्होंने विपक्ष को कमजोर और नीचा दिखाने की कोशिश तो की लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। यह सवाल अब भी कायम है कि प्रधानमंत्री जब दिल्ली में थे तो जवाब देने राज्यसभा में क्यों नहीं गए माना जा रहा है कि वे सीजफायर पर लोकसभा में दिया गया बयान दोहराना नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और नाराज करे। यह भी माना जा रहा है कि भारत के ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार करने की वजह से जुर्माना लगाने का ट्रंप का फैसला लोकसभा में दिए मोदी के भाषण से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बात से नाराज है कि उन्हें सीजफायर का श्रेय नहीं दिया जा रहा है। यह बात उन्होंने 29 जुलाई को एक इंटरव्यू में भी कही। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम के एलान से भारतीय जनमत के एक बड़े हिस्से में पैदा हुए गुस्से को समझा जा सकता है। ये प्रतिक्रिया संकेत है कि भारतीय शासक समूहों के अपनी सुविधा से पाकिस्तान कार्ड' खेलने के रवैये से लोग अब आजिज़ आ चुके हैं। वे उनकी इन सुविधाओं' को समझने भी लगे हैं। यह बात वर्तमान शासक दल और उससे जुड़े समूहों ने ही फैलाई कि गोली और बोली' साथ-साथ नहीं चल सकती। इसी क्रम में कहा गया कि दहशतगर्दी के आका देश के साथ खेलना जारी नहीं रखा जा सकता। अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि खून और पानी (सिंधु समझौते के तहत) साथ-साथ नहीं बह सकते।' चूंकि ऐसी बातों पर देश में राजनीतिक आम सहमति है और मीडिया इनके पक्ष में जोर-शोर से प्रचार करता है, तो स्वाभाविक है कि आम लोग इसे व्यवहार का उचित पैमाना समझते हैं। मगर अब ऐलान हुआ है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई में होगा। उसमें 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का मैच होगा। आखिर आम लोग इसे कैसे गले उतार सकते हैं तो ये सहज प्रतिक्रिया आई है कि सब धंधे की बात है। जहां पैसे के बड़े दांव लगे हो, वहां देशभक्ति पृष्ठभूमि में डाल दी जाती है। किस खेल में या किस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से भारत खेले या ना खेले, यह मनमाने ढंग से तय किया जाता रहा है। इसलिए बीसीसीआई और अन्य खेल संस्थानों के साथ-साथ भारत सरकार की नीयत पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड में वहां एक अधिकारी की कार्य क्षमता पर हाई कोर्ट ने इस आधार पर सवाल उठाया है कि उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आती है। यह हैरान करने वाली बात है। धाराप्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकना भारत में किसी अधिकारी की अयोग्यता कैसे हो सकती है यह मामला उत्तराखंड के नैनीताल का है, जहां से एडीएम रैंक के अधिकारी ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुणाथन नरेंद्र और जस्टिस आलोक महारा की पीठ के सामने हिंदी में अपनी बात रखी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि वे हिंदी में अपनी बात क्यों रख रहे हैं इसके जवाब में एडीएम ने कहा कि वे अंग्रेजी लिख और समझ सकते हैं लेकिन धाराप्रवाह बोल नहीं सकते हैं। इस बात पर चीफ मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि वे बताएं कि अगर कोई अधिकारी अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो इस पद पर रह कर वह प्रभावी तरीके से कैसे काम कर सकता है कर्नाटक हाई कोर्ट में पहली बार जज बने जस्टिस नरेंद्र आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रहे हैं और उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बहरहाल यह चर्चा का मुद्दा बन गया है कि हिंदी क्षेत्र में किसी अधिकारी को अंग्रेजी नहीं आती है तो उसकी कार्यक्षमता कैसे प्रभावित हो सकती है अगर उसे हिंदी नहीं आती तो यह सवाल जरूर उठ सकता था। लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लिए कोई संकट आता देख रहे हैं। इस बात का संकेत उनकी हाल की गतिविधियों से मिलता है। पिछले दिनों उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलने के लिए बुलाया। दोनों की यह मुलाकात ढाई साल बाद हुई। इस बीच लोकसभा का चुनाव हुआ और गोंडा की सीट से ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को भाजपा ने टिकट दिया। चुनाव के दौरान भी उनकी मुलाकात योगी से नहीं हुई। वे अपने दम पर चुनाव लड़े और जीते। चुनाव प्रचार के दौरान एक पत्रकार ने उनसे कहा था कि गोंडा में भाजपा हार रही है तो ब्रजभूषण ने कहा था कि अगर भाजपा गोंडा में हार रही है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत रही है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह 31 महीने के बाद योगी से मिले। मुलाकात के बाद कहा, %%योगी बड़े हैं तो बड़े को ही झुकना होता है। उन्होंने बुलाया तो हम गए।'' ब्रजभूषण ने साफ किया कि वे खुद मिलने नहीं गए। योगी झुके और बुलाया तो वे मिलने गए। अब सवाल है कि योगी क्यों झुके क्या राजपूत एकता का प्रयास हो रहा है गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार और झारखंड के राजपूत समुदाय में खासा असर रखते हैं। योगी ने बुला कर मुलाकात की है तो इसका मतलब है कि योगी ने आपात तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि भाजपा आलाकमान उनके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो उससे निबटा जा सके। कांग्रेस सांसद शशि थरूर वैसे तो हर साल आम की पार्टी देते हैं लेकिन इस बार की पार्टी कुछ खास थी। इस बार की पार्टी में राजनीति से ज्यादा कूटनीति दिखी।

इसीलिए ऐसा लगा कि थरूर अपनी पोजिशनिंग में लगे हैं। आमतौर पर उनकी पार्टी में सभी दलों के नेता बुलाए जाते हैं लेकिन इस बार उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में राजनयिक आमंत्रित थे। दुनिया भर के देशों के दूतावासों के अधिकारियों को थरूर ने बुलाया था और वे आए भी थे। कहा जा रहा है कि थरूर जब से पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को बताने गए भारत के एक डेलिगेशन का नेतृत्व करके लौटे हैं तब से वे अपने विदेशी संपर्कों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आम की पार्टी में विदेशी मेहमानों और राजनयिकों को बुला कर थरूर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वे एक प्रभावी विदेश मंत्री हो सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनके भाजपा में जाने और विदेश मंत्री बनने की चर्चा थम गई है। बहरहाल, थरूर की आम पार्टी की राजनीति की बात करे तो उसमें उनके लिए बहुत संभावना नहीं दिखीं। कांग्रेस के थोड़े से नेता जरूर पहुंचे, लेकिन वे सभी केरल के थे और उनका भी मकसद यह पता लगाना था कि पार्टी में क्या हो रहा है और कौन-कौन लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति देख कर तो लगा कि वहां अब थरूर अलग-थलग पड़ गए हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

डॉ. सुभाष सूद को राष्ट्र टाइम्स के 45वें स्थापना दिवस पर भव्य सम्मान

— चिकित्सा जगत की चमकता सितारा बना ट्रांस-यमुना का यह नामचीन सर्जन

नई दिल्ली (आकाश शक्य) नगर चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवाएं देने वाले वरिष्ठ जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. सुभाष सूद को राष्ट्र टाइम्स द्वारा उसके 45वें स्थापना दिवस के गौरवमयी अवसर पर भव्य रूप से सम्मानित किया गया। राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने डॉ. सूद को विशेष स्मारिका, शॉल तथा स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया और उनके चिकित्सकीय योगदान को समाज के लिए अनुकरणीय बताया। डॉ. सूद का नाम ट्रांस-यमुना क्षेत्र में चिकित्सा सेवा का पर्याय बन चुका है। वर्ष 1983-84 में वालिया नर्सिंग होम की स्थापना के समय से लेकर अब तक वे क्षेत्र के हजारों मरीजों की सेवा में समर्पित हैं। वे 38 वर्षों से अधिक समय से लगातार स्वास्थ्य सेवा में सक्रिय हैं और आज भी अपनी विद्वता और करुणा से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत गौरवशाली है – उन्होंने पी.जी.आई. चंडीगढ़, एन.ए.एम.एस. दिल्ली, तथा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स (इंग्लैंड) से उच्चतम चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की। वे इस क्षेत्र में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत करने वाले अग्रदूतों में गिने जाते हैं। इस अवसर पर शर्मा नर्सिंग होम के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रमोद शर्मा (एम.डी.) ने भी डॉ. सूद के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान की भूरि-भूरि सराहना की। उन्होंने कहा डॉ. सुभाष सूद सिर्फ एक कुशल सर्जन ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। उनका जीवन समर्पण, सेवा और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। मैंने स्वयं उन्हें वर्षों से देखा है – उनका हर कदम मरीजों के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आता है। ट्रांस-यमुना की चिकित्सा परंपरा में उनका योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

कांग्रेस नेता, सुभाष चोपड़ा का भव्य सम्मान समारोह—पत्रकारिता और राजनीति के दो महान स्तंभों की अभूतपूर्व भेंट

नई दिल्ली (आकाश शक्य) की राजनीति के एक अनुभवी, ईमानदार और जनसमर्पित चेहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ विधायक श्री सुभाष चोपड़ा का सम्मान उनके आवास पर एक गरिमामयी समारोह में किया गया। यह विशेष अवसर राष्ट्र टाइम्स के 45वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने उन्हें शॉल, प्रतीक चिन्ह और एक विशेष स्मारिका भेंट की।

यह एक सम्मान नहीं था, बल्कि सत्य, सेवा और संवेदनशीलता की उस विरासत का उत्सव था जिसे दोनों महान हस्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित किया है।

52 वर्षों की निर्भीक पत्रकारिता का सम्मान

श्री सुभाष चोपड़ा ने श्री विजय शंकर चतुर्वेदी के पत्रकारिता जीवन की विशेष सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में जब पत्रकारिता कई बार मार्ग से भटकती नजर आती है, ऐसे दौर में राष्ट्र टाइम्स और श्री चतुर्वेदी जैसे निर्भीक संपादक लोकतंत्र की असली ताकत हैं। उनकी लेखनी ने सदैव जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, और सच्चाई को किसी दबाव या भय के बिना प्रकाशित किया है।÷

श्री चतुर्वेदी का पत्रकारिता सफर 52 वर्षों से अधिक का है, जिसमें उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सैकड़ों धारदार, ईमानदार और तथ्यपरक लेख लिखे हैं। उनका उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि समाज को जगाना और दिशा देना रहा है।

सुभाष चोपड़ा ङ्क जनता के नेता, संवेदनशील समाजसेवी

वहीं श्री चतुर्वेदी ने भी श्री सुभाष चोपड़ा के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को गहराई से याद करते हुए कहा-

> ÷श्री चोपड़ा न केवल एक अनुभवी राजनेता हैं, बल्कि वे दिल से एक जनसेवक हैं। उन्होंने हमेशा झुग्गी-झोपड़े में रहने वाले गरीब तबके, बेसहारा लोगों और जरूरतमंद परिवारों की पुनर्वास और सहायता के लिए अविराम कार्य किया है।÷

उनका राजनीतिक जीवन किसी पद या सत्ता की लालसा से नहीं, बल्कि जनता की सेवा और संघर्षों से जुड़ा हुआ रहा है। उन्होंने दिल्ली की राजनीति में साफ़-सुथरी छवि, विकासोन्मुखी दृष्टिकोण और जनभावनाओं के सम्मान को बनाए रखा।

पत्रकारिता और राजनीति का अनोखा संगम

दोनों हस्तियों ने एक-दूसरे के योगदान को नमन करते हुए यह भी जताया कि

> पत्रकारिता और राजनीति, दोनों लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ हैं। जब ये दोनों ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, तभी समाज प्रगति और न्याय के रास्ते पर चलता है।

राष्ट्र टाइम्स की यह पहल न केवल पत्रकारिता और राजनीति के संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि लोकतंत्र में सत्य, संवेदना और संघर्ष की परंपरा अभी भी जीवित है। यह सम्मान समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया – कि चाहे आप पत्रकार हों या राजनेता, ईमानदारी, जनसेवा, और दूरदर्शिता ही वह मूल्य हैं जो व्यक्ति को इतिहास में स्थान दिलाते हैं।

राष्ट्र टाइम्स और श्री विजय शंकर चतुर्वेदी की यह पहल आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती है कि मूल्य आधारित कार्य और सच्ची निष्ठा ही व्यक्ति की असली पहचान है।

प्रदेश सरकार राय के हर क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से करवा रही है विकास कार्य-मंत्री कृष्ण कुमार बेदी

चंडीगढ़ । हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि सच्चे जन प्रतिनिधि का एक मात्र धर्म जनसेवा होता है। निस्वार्थ भाव से जनभावनाओं के अनुरूप जनहित के कार्य करवाना और आमजन की समस्याओं का समाधान करना ही सच्चे एवं सार्थक जनसेवक की पहचान होती है। मौजूदा राय सरकार निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं बराबर विकास कार्य करवा रही है। हरियाणा में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा पंजाब जैसे पडोसी राय में भी है। अन्य इलाकों की तरह नरवाना भी भविष्य में विकास का उदाहरण बने, इसके लिए वे दिन-रात प्रयासरत्त हैं। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी शनिवार देर सांय नरनावा विधानसभा हलका के गांव डिंडोली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि 17 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव में जनसमर्थन के लिए नरवाना क्षेत्रवासियों का आभार जताने और करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर मंत्री ने वाल्मीकि चौपाल तथा जिम्म हाल का शिलान्यास किया। इनके निर्माण पर करीब 20 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा मंत्री ने लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा की। इन सभी विकास कार्यों के एस्टिमेट बनाकर जल्द सम्बन्धित विभागों को भिजवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत को अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने 51 लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान देने के लिए भी कहा। इस प्रकार गांव में लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे।

नरवाना वासियों के लिए विकास के मामले में 17 अगस्त का दिन वरदान साबित होगा

अपने मन को अपना अच्छा दोस्त बनाइये- बीके सुनीता

शहर के सैकड़ों प्रतिष्ठित व्यापारियों को राखी बांधकर, विकारों से मुक्त रहने का कराया संकल्प

पानीपत ।

आज प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सेक्टर-12 स्थित ओमशान्ति भवन में व्यापारियों के लिए एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विषय आनन्द उत्सव को राजयोगिनी बीके सुनीता बहन ने स्पष्ट किया। इस मौके पर जी आर सी निदेशक बीके भारत भूषण, सर्कल इंचार्ज बीके सरला दीदी और ब्रह्माकुमार गायक ओमप्रकाश सहित शहर के सैकडों व्यापारीगण उपस्थित रहे। अपने विषय पर बोलते हुए बीके सुनीता बहन ने कहा कि जीवन को खुशियों से भरना चाहते हो तो अपने मन को अपना अच्छा दोस्त बनाइये। खुद से प्यार कीजिये। दुसरो से कुछ लेने की उम्मीद मत रखिए। सबको स्नेह व सहयोग दीजिए फिर देखना आपके रिश्ते सभी के साथ अछे हो जाएंगे।

और आपका जीवन आनन्द का उत्सव बन जायेगा । बहन जी ने आगे कहा कि खाना खाने से पहले परमात्मा पिता को जरूर याद करें। और रोज रात सोने से पहले उन सभी आत्माओं से क्षमा ले लीजिए जिनको आपने जाने अनजाने मन, वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाया हो। ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर निदेशक बी के भारत भूषण ने शुभकामना देते हुए कहा कि अगर जीवन रूपी यात्रा को आसान बनाना है तो उसका एक ही सहज तरीका है, सबसे दुवाएं लो ओर सबको दुवाएं दो। हर रोज एक श्रेष्ठ कर्म व पुण्य का कार्य जरूर करो। फिर कहा कि उपर वाला जो करता है उसकी हर बात में कल्याण समाया है, लेकिन मनुष्य वर्तमान में दिखाई देने वाले हानि-लाभ को देखकर परेशान हो जाता है। कार्यक्रम के सह आयोजक उद्योगपति वेद प्रकाश छाबड़ा ने आये हुए सभी मेहमानों का शब्दों के माध्यम से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सर्कल इंचार्ज बीके सरला बहनजी ने राजयोग का अभ्यास कराया और कहा परमात्मा से कभी भी शिकवे व शिकायत मत करना, केवल शुक्रिया करते चलो तो जीवन खुशहाल हो जायेगा।

साथ ही बहन जी ने कार्यक्रम मे आये हुए व्यापारियों को राखी बांधकर मुख मीठा कराया और सभी को विकारों से मुक्त रहने का संकल्प भी कराया। सभा में शहर के सैकड़ों प्रतिष्ठित व्यापारियों में राजेन्द्र छाबड़ा,अर्जुन, नितिन अरोड़ा, राजेन्द्र खुराना, बलदेव, सनल, सुनील बवेजा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम मे मंच संचालन बी के योति बहन ने किया।

सुनील जागलान ने रक्षाबंधन पर विशेष पहल की शुरू, बहनें इस बार भाइयों से लें ये अनोखा वचन

चंडीगढ़। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और सामाजिक सुधारक सुनील जागलान, जो अपनी 'गाली बंद घर अभियान' के लिए विख्यात हैं। उन्होंने इस बार रक्षाबंधन को एक सार्थक संदेश के साथ मनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस अभियान के तहत जागलान ने देशभर की लडकियों को पहले फेज में 3,000 से अधिक पोस्टकार्ड भेजे हैं, जिसमें बहनों से आग्रह किया गया है कि वे इस रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से एक अनोखा वचन लें दैनिक जीवन में मॉ-बहन-बेटी को गाली-गलौज और अपमानजनक भाषा का उपयोग न करने का संकल्प। इस अभियान का नाम है 'रक्षाबंधन की डोर, गाली बंधन की ओर'। सुनील जागलान ने कहा, रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्यार का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक-दूसरे की रक्षा का वचन भी है। इस बार हम इसमें एक नया आयाम जोड़ रहे हैं ङ्क भाषा और सम्मान की रक्षा। उन्होंने बहनों से अपील की है कि वे राखी के पवित्र धागे को सम्मानजनक भाषा का प्रतीक बनाएं और अपने भाइयों को इस संकल्प के लिए प्रेरित करें। इस संदेश को और व्यापक बनाने के लिए जागलान ने महिलाओं को निमंत्रण दिया है कि वे अपने भाइयों को राखी बांधते समय और उनके इस वचन को लेते समय वीडियो बनाएं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाएंगे, और चुनिंदा प्रतिभागियों को आगामी समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जागलान ने बताया कि उनकी 'गाली बंद घर अभियान' के तहत 11 वर्षों की गहन सर्वेक्षण के नतीजे हाल ही में जारी किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 70,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया, जिसमें छात्र, अभिभावक, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, वकील और अन्य पेशेवर शामिल थे। सर्वे के अनुसार, भारत में लगभग 55त्न पुरुष और महिलाएं अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अपशब्दों का उपयोग करते हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा सबसे अधिक 80फीसदी है, इसके बाद पंजाब, जबकि कश्मीर में सबसे कम 15त्न दर्ज किया गया। सर्वे में उत्तर प्रदेश में 11,300, मध्य प्रदेश में 8,400, राजस्थान में 6,100, पंजाब में 4,200, महाराष्ट्र में 3,800 और दिल्ली, गुजरात, बिहार, कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा और पश्चिम बंगाल में अन्य मामले सामने आए। जागलान ने जोर देकर कहा कि अपशब्दों का उपयोग एक सामाजिक बुराई है। जैसे भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं, वैसे ही उन्हें एक दयालु और सम्मानजनक समाज बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यह अभियान हर घर से भाषा और व्यवहार में संवेदनशीलता लाने की दिशा में एक कदम है। आगे की योजना के बारे में बताते हुए जागलान ने कहा कि हम जल्द ही दक्षिण एशिया में इसी तरह के सर्वेक्षण आयोजित करने और विश्व स्तर पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली अपमानजनक भाषा को समाप्त करने की दिशा में काम करने की योजना बना रहे हैं। अपशब्दों का उपयोग एक मानसिक बीमारी है, और कई शब्द सीधे तौर पर महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। यह अभियान न केवल रक्षाबंधन के पर्व को एक नया अर्थ दे रहा है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की एक मजबूत नींव भी रख रहा है। आइए, इस रक्षाबंधन पर हम सभी सम्मानजनक भाषा के लिए संकल्प लें और एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ाएं। सुनील जागालान द्वारा काफ़ी क्षेत्रों में गाली बंद अभियान चलाया जा रहा है जिसकी तारीफ़ में ब्रिटेन के द गार्जियन ने भी की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉय बिडेन द्वारा एक पत्रकार को गाली देने पर अन्तर्राष्ट्रीय मैगज़ीन कॉस्मोपॉलेटिन ने लिखा कि भारत के एक गॉव का सरपंच सुनील जागलान महिला संबंधी गाली को रोकने के प्रयास में अभियान चला रहा है वहीं व्हाइट हाऊस में रहने वाला राष्ट्रपति मॉ की गाली दे रहा है । यह नसीहत के तौर पर लिखा गया तथा इस खबर ने अन्तर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरीं। ग़ौरतलब है कि सुनील जागलान पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास के विषय पर कार्य कर रहे हैं जिसका असर देखने को मिल रहा है तथा देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मानक ऐंजसीयों ने भी सुनील जागालान के अभियान को असरदार बताते हुए तारीफ़ की है । सुनील जागलान ने बेटी बचाओ से लेकर सेल्फ़ी विद डॉटर, बेटियों के नाम नेमप्लेट, पीरियड चार्ट, लडकियों की शादी की उम्र 21 करने लिए अभियान, एक पेड़ लाडो के नाम, सेल्फ़ी अंगेस्ट डॉवरी, विमेन हैप्पीनैस चार्ट, लाडो पंचायत जैसे सैकड़ों अभियान शुरू किए हैं जो देश विदेशों में प्रशंसा पा चुके हैं ।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी इनके अभियानों की दस बार तारीफ कर चुके हैं।

मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन ने किया हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री के आवास की ओर कूच

पानीपत ।

केंद्रीय श्रमिक संगठन, एआईयूटीयूसी से सम्बन्धित मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा रजि.नं.2077 के आह्वान पर आज प्रदेश भर से हजारों मिड-डे-मील कूक स्थानीय देवीलाल पार्क में इकट्ठी हुई। वहां से एक विशाल जुलूस की शक्ल में अपनी मांगों के नारे लगाते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री के आवास की ओर कूच किया। मिड-डे-मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना बन्द करो, यूनियन नेत्री कुसुम पांचाल को बहाल करो, इन्कलाब जिंदाबाद जैसे नारों से आसमान गूंज उठा। बैनर, पट्टिकाओं से सुसज्जित, अभूतपूर्व अनुशासन के साथ शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच कर जुलूस धरने में बदल गया। यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने वहां अपनी 11 सूत्री प्रमुख मांगों का एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री के नाम उनके प्रतिनिधि मास्टर गुलाब सिंह को दिया और उनसे आग्रह किया कि शिक्षा मंत्री यथाशीघ्र यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को बुला कर बातचीत करें और यूनियन की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक अविलंब पूरा करें। यूनियन नेत्रियों ने बताया कि मिड-डे-मील कर्मी सबसे गरीब परिवारों से आती हैं। उनमें से बहुत सी विधवा हैं। गृहस्थी का पूरा खर्च उन्हें ही उठाना पड़ता है। सरकार महज 7,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देती है। परन्तु यह भी सिर्फ 10 महीने का ही दिया जाता है।

जबकि स्कूलों में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन दिया जाता है। न्याय का तकाजा है कि सरकार मिड-डे-मील कर्मियों को भी 12 महीने का मेहनताना दे और इसे बढ़ाकर प्रदेश में श्रमिक के लिए लागू न्यूनतम वेतन के समान करे। यूनियन की प्रदेश प्रधान राजबाला पालुवास ने बताया कि यह 7,000 रु. मासिक मानदेय भी उन्हें कई कई महीनों तक नहीं मिलता।

हमारी मांग है कि सरकार हमें पूरे 12 महीने का मानदेय श्रमिक के लिए लागू न्यूनतम वेतन के समान हर महीने की 7 तारीख तक नियमित रूप से भुगतान करे। मिड डे मील कर्मियों को सरकार द्वारा साल में दो ड्रेस के महज 800 रुपए दिए जाते हैं।

इतने में तो सिलाई के भी पूरे नहीं होते। दो ड्रेस के लिए कम से कम 3,000 रुपए सालाना दिए जाएं। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए और रिटायर होने पर एकमुश्त 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए।

निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएं। यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने रोषपूर्वक बताया कि सेवारत मिड-डे-मील कूकों को मनमाने ढंग से झूठे आरोप लगाकर हटा दिया जाता है। हमारी यूनियन की महासचिव कुसुम पांचाल जो पूरे प्रदेश की कुकों की आवाज बन रही थी, उसे बिना कोई कारण बताए घोर मनमाने तरीके से नौकरी से हटा दिया गया। हम पुरजोर मांग करती हैं कि यूनियन नेत्री कुसुम पांचाल को तुरंत प्रभाव से कुक की नौकरी पर बहाल किया जाए और किसी भी मिड-डे-मील कर्मी को हटाया नहीं जाए।

मिड-डे -मील कर्मियों ने कहा कि सरकार की चिकनी-चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। ज्ञापन में दी गई 11 सूत्री बिल्कुल जायज मांगों को मंजूर कर हमारी समस्याओं का अविलंब समाधान किया जाए। अन्यथा आंदोलन को तीव्र करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं बचता है। मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन के आज के इस विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन की प्रदेश प्रधान राजबाला पालुवास और महासचिव कुसुम पांचाल, पुष्पा महेन्द्रगढ़, मुनेश देवी रेवाड़ी, अत्री पानीपत, रेखा सोनीपत, देवकी देवी नूंह, सुमन, बिमला दादरी, मीरा भिवानी, सन्तरा व मुकेश हांसी और एआईयूटीयूसी के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठी, प्रदेश सचिव हरि प्रकाश व सूबे सिंह यादव, राजकुमार बासिया, मेहरसिंह, धर्मबीर ने किया। पानीपत रैली में पूरे हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, हिसार, भिवानी, दादरी, रोहतक, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, झजर, नूंह, गुड़गांव, कैथल, करनाल आदि विभिन्न जिलों से मिड-डे-मील कर्मियों ने जोश-खरोश के साथ सक्रिय भागीदारी की।

स्कूलो में आवंटित टैब बने खिलौना, ना सिम और ना इंटरनेट दे पाई सरकार- हुड्डा

चंडीगढ़ ।

बीजेपी सरकार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी स्कूलों को बंद कर सकती है, ना कि कोई नया स्कूल या नई योजना शुरू कर सकती है। अगर गलती से इस सरकार ने कोई योजना शुरू भी कर दी, तो खुद ही उसका बंटाधार कर डाला। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा इस सरकार की स्कूलों में टैब बांटने वाली योजना पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 700 करोड रुपए की लागत से शुरू की गई इस योजना का सरकार ने खुद ही बेड़ा गर्क कर डाला। विद्यार्थियों को दिए गए टैब खिलौना बनकर रह गए हैं। क्योंकि बिना सिम और बिना इंटरनेट के अप्रैल महीने से ये पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं। खबरें यहां तक सामने आ रही हैं कि यह सरकार अपनी ही योजना को बंद करने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी पहले ही कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब, एससी व ओबीसी बच्चों को दी जानी वाली वजीफा योजना को लगभग समाप्त कर चुकी है। कांग्रेस की ही स्पैट व गरीब स्कूली खिलाड़ियों को आर्थिक मदद की योजना को भी बंद किया जा चुका है। हुड्डा ने कहा कि टैब योजना की तरह इस सरकार ने खुद की चलाई आयुष्मान योजना को भी खेल बनाकर रख दिया है। यही सलूक फसल बीमा योजना और कौशल रोजगार निगम के साथ हुआ है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जमकर झूठ फैलाया कि उनकी सरकार ने कौशल निगम के तहत आने वाले सभी सवा लाख कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। अब उन्हें रिटायरमेंट तक कोई नौकरी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब से तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई है, लगातार कौशल कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब इसको लेकर एक और नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो लोग कौशल निगम में 5 साल से कम समय से कार्य कर रहे हैं, उनका नौकरी से निकलना तय है। इसीलिए माम कौशलकर्मी आज बीजेपी के वादों पर भरोसा करके और उन झूठे वादों के बहकावे में जाकर बीजेपी को वोट करके पछता रहे हैं।

रोटरी क्लब पानीपत सॉलिटेयर का प्रथम स्थापना समारोह सम्पन्न — सीए गौरव सतीजा बने पहले अध्यक्ष

पानीपत ।

रोटरी क्लब पानीपत सॉलिटेयर ने रोटरी वर्ष 2025-26 के लिए अपना प्रथम स्थापना समारोह बड़े उत्साह एवं सेवा भाव के साथ आर्य समाज, मॉडल टाउन, पानीपत में सम्पन्न किया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीडीजी रोटेरियन रणजीत के. भाटिया, गेस्ट ऑफ ऑनर पीपी रोटेरियन सुदर्शन चुग एवं एजी रोटेरियन विभास कैला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ज़िले के अन्य वरिष्ठ रोटेरियन्स एवं गणमान्य अतिथियों ने भी भाग लिया। समारोह के दौरान, सीए गौरव सतीज़ा को नवगठित क्लब का प्रथम अध्यक्ष (चार्टर प्रेसिडेंट) नियुक्त किया गया, जबकि सीए कुनाल कथूरिया ने सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सीए गौरव सतीजा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा रोटरी क्लब पानीपत सॉलिटेयर भले ही एक नया क्लब है, लेकिन इसे स्थापित करने वाले मार्गदर्शकों का अनुभव 15-20 वर्षों का है। हमारा लक्ष्य भी वही है समाज में

सकारात्मक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध सेवाएं देना। रोटरी के मूल मंत्र "Service Above Self" (स्वार्थ से ऊपर सेवा) को साकार करते हुए, क्लब द्वारा कन्या गुरुकुल (आर्य समाज, मॉडल टाउन) की छात्राओं के लिए वाटर कूलर, कुर्सियाँ और बेंच प्रदान की गईं, जिससे उनकी शिक्षा का वातावरण और अधिक सुविधाजनक व गरिमापूर्ण बन सके। इस अवसर पर अध्यक्ष गौरव सतीजा ने आगे कहा रोटरी ने हमें देने की सच्ची खुशी सिखाई है। यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम इन बालिकाओं की पढ़ाई को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें। समारोह की विशेषता यह रही कि सभी उपस्थितजनों ने अपने गुरु व ईश्वर को याद करते हुए एक भावनात्मक मौन रखा, जिसके पश्चात अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एक प्रेरणादायक कविता ने पूरे वातावरण को भाव-विभोर कर दिया।

कन्या गुरुकुल की छात्राओं को उपहार स्वरूप दिया गया फर्नीचर व वाटर कूलर

इस गरिमामय अवसर पर अनेक वरिष्ठ रोटेरियन गण भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से – पीपी रोटेरियन अतुल चोपड़ा, पीडीजी रोटेरियन रमेश बजाज, पीपी रोटेरियन अनिल दिलोरी, रोटेरियन डॉ. प्रदीप वर्मा, रोटेरियन सुरिंदर भाटिया, रोटेरियन रोहित सपरा, रोटेरियन केवल गर्ग, रोटेरियन शिव मल्होत्रा, पीडीजी रोटेरियन रमन अनेजा, रोटेरियन रमन टक्कर एवं रोटेरियन डॉ. प्रदीप वर्मा प्रमुख रहे। रोटरी क्लब पानीपत सॉलिटेयर का उद्देश्य है कि वह रोटरी आंदोलन में एक अद्वितीय और प्रभावशाली इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाए – बिलकुल एक "Solitaire" हीरे की तरह जो दुर्लभ, मूल्यवान और उद्देश्य की चमक से दमकता है।

मस्जिद से तिरंगा हटाकर लगाया भगवा झंडा, आरोपी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इन्कार

चंडीगढ़ । गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा ध्वज हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा लगाने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस मनीषा बत्रा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी विकास तोमर के खिलाफ आरोप अस्पष्ट या सामान्य नहीं थे, बल्कि विशिष्ट थे और उसके और अन्य आरोपियों के बीच बातचीत से इसकी पुष्टि होती है। जस्टिस बत्रा ने सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। सार्वजनिक व्यवस्था व सांप्रदायिक शांति पर इसके संभावित प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा कोई असाधारण या अपवादात्मक परिस्थिति दर्ज नहीं की गई है जिसके आधार पर गिरफ्तारी-पूर्व जमानत दी जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जुलाई को गुरुग्राम के बिलासपुर में शिकायत प्राप्त हुई थी कि असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद से राष्ट्रीय ध्वज हटाकर वहां भगवा झंडा लगा दिया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय ने 15 जुलाई को वर्तमान याचिकाकर्ता तोमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने अपने आदेश में कहा था कि भारत जैसे महान देश में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो अपने तुच्छ लक्ष्यों और गलत विचारधाराओं के कारण समाज के सामाजिक ताने-बाने को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति, जिसके दिल में थोड़ी सी भी देशभक्ति हो, ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। याची के वकील ने तर्क दिया कि पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनका नाम एफआईआर में भी नहीं था। हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि आरोपी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे।

स्कूल फीस कंट्रोल बिल पर घमासान, आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले- सिर्फ पैरेंट्स की जेब ढीली होगी

नई दिल्ली । दिल्ली की भाजपा सरकार मानसून सत्र में स्कूल फीस कंट्रोल बिल लाने जा रही है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है. पार्टी का कहना है कि सरकार निजी स्कूलों और शिक्षा माफिया को खुली छूट देने जा रही है, जबकि पैरेंट्स की आवाज को दबाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि सरकार ने जो नया फीस कंट्रोल बिल तैयार किया है, उससे न सिर्फ पैरेंट्स की जेब ढीली होगी बल्कि निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूलने का खुला रास्ता मिल जाएगा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सबसे खतरनाक बात यह है कि बिल में स्कूलों की ऑडिट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है. यानी अब यह जानने का कोई तरीका नहीं रहेगा कि स्कूल कितना कमा रहा है, उसकी असली जरूरत क्या है और क्या फीस बढ़ाना जायज है. उन्होंने कहा, जब तक ऑडिट नहीं होगा, सरकार को यह पता ही नहीं चलेगा कि स्कूलों को फीस बढ़ाने की जरूरत भी है या नहीं. जब सरकार ने ऑडिट का वादा किया था, तो अब उसे कानून से क्यों हटा दिया गया अब तक अगर एक भी पैरेंट्स को फीस बढ़ोतरी पर आपत्ति होती थी, तो वह शिक्षा निदेशालय से शिकायत कर सकता था. लेकिन नए कानून में यह अधिकार छीन लिया गया है. अब फीस वृद्धि की शिकायत तभी होगी, जब कम से कम 15फीसदी पैरेंट्स साइन करें. सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, यह तो वैसा ही है जैसे मोहल्ले में सीवर जाम हो गया और MCD कहे कि पहले 15फीसदी मोहल्ले वालों से हस्ताक्षर लाओ, तभी सीवर खुलेगा. उन्होंने पूछा कि अगर किसी स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई पैरेंट्स 450 अन्य पैरेंट्स को कैसे ढूंढेगा, समझाएगा और साइन कराएगा यह तो शिकायत दर्ज ही न हो, इसके लिए एक जाल बिछाया गया है. बिल के अनुसार, हर स्कूल में फीस निर्धारण के लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसमें 5 सदस्य स्कूल की तरफ से और 5 पैरेंट्स की तरफ से होंगे. लेकिन इसमें भी एक बड़ी चाल है. सौरभ का कहना है कि स्कूल मालिक अपने मनपसंद लोगों को ही कमेटी में शामिल करेगा. पैरेंट्स के सदस्य लॉटरी से चुने जाएंगे, लेकिन यह लॉटरी भी स्कूल ही निकालेगा. ऐसे में स्कूल अपने लोगों को पैरेंट्स प्रतिनिधि बनाकर कमेटी में भेजेगा और मनमानी फीस बढ़ा देगा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले भी जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन की बात होती थी, तो स्कूल अपने ही लोगों को एडमिशन दे दिया करते थे. यह कोई नई बात नहीं है. अब वही तरीका फीस निर्धारण कमेटी में दोहराया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में जैसे ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ, कई स्कूलों ने अचानक 60-80फीसदी तक फीस बढ़ा दी. भारद्वाज ने सवाल उठाया कि डीपीएस द्वारका के बाहर पैरेंट्स ने दिन-रात धरना दिया, लेकिन स्कूल ने बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया, लाइब्रेरी में बैठाया गया. कुछ स्कूलों ने तो बाउंसर भी लगा दिए थे. क्या यही शिक्षा व्यवस्था है.

नहर में गिरी बोलेरो, एक ही परिवार के 9 सदस्यों समेत 11 लोगों की मौत

गोंडा ।

यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ही परिवार के 9 लोग हैं। बोलेरो में 16 लोग थे। 4 को शीशा तोड़कर स्थानीय लोगों ने बचा लिया। अभी 10 साल की बची लापता है। सशस्त्र टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। सभी जल चढ़ाने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे।

हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो से एक भी शख्स खुद बाहर नहीं निकल पाया। बारिश के चलते नहर में लबालब पानी था। नहर में गिरते ही गाड़ी पूरी तरह से डूब गई और उसके गेट लॉक हो गए। अंदर बैठे लोग छटपटाते रहे। तड़प-तड़पकर उनकी मौत हो गई। जहां हादसा हुआ, वहां आसपास ग्रामीण थे। बोलेरो नहर में गिरती देख वह बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन गेट नहीं खोल पाए। रस्सी बांधकर बोलेरो को किनारे तक ले आए, तब जाकर गाड़ी का कुछ

हिस्सा बाहर आया। बमुश्किल खिड़की का शीशा तोड़कर 4 लोगों को बाहर निकाला। हादसा रविवार सुबह 10 बजे इटियाथोक थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है। इसमें सड़क पर 11 लाशें पड़ी हुई हैं। किसी को बेटी तो किसी को बेटा सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा। पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त कार की स्पीड 60 किमी प्रति घंटे थी।

मृतकों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे

मृतकों में 6 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे हैं। सीहागांव निवासी प्रह्लाद की पत्नी बीना (44), दो बेटियां काजल (22), महक उर्फ रिंकी (14), प्रह्लाद के चौथे नंबर के भाई रामकरण (36), रामकरण की पत्नी अनसुईया (34), बेटे शुभ (7), बेटी सौम्या (9), प्रह्लाद के सबसे छोटे भाई रामरूप की पत्नी दुर्गेश नंदिनी (35), बेटा अमित (14) शामिल हैं। वहीं, रामरूप की एक बेटी रचना (10) लापता है। इसके

गाड़ी में छटपटाते रहे, बाहर नहीं निकल पाए; जल चढ़ाने मंदिर जा रहे थे

अलावा प्रह्लाद के पड़ोसी रामललन वर्मा की पत्नी संजू (26) और बहन गुड़िया उर्फ अंजू (20) की मौत हुई। हादसे में प्रह्लाद का एक बेटा सत्यम और एक बेटी पिंकी घायल हैं। पड़ोसी रामललन और ड्राइवर सीतारमण भी घायल हैं।

सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली ।

देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर रविवार को एक गंभीर घटना सामने आई, जब उनके नागपुर स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 8:46 बजे आई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई की। कुछ ही घंटों में धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आई, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस कॉल के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होते ही कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने तत्काल ही स्थानीय पुलिस थाने को मामले की जानकारी दी और जांच में जुट गई। धमकी मिलने के बाद

पुलिस ने तुरंत गडकरी के घर के आसपास के इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने गडकरी के घर का बारीकी से निरीक्षण किया। सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बाद पुलिस ने आरोपी की खोज शुरू की। कुछ घंटों बाद पुलिस ने आरोपी को नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उमेश विष्णु राउत के रूप में हुई। उमेश विष्णु राउत नागपुर के मेडिकल चौक स्थित एक देसी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी है। गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, यह जांच का विषय बना हुआ है। गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद से उनके समर्थक और परिवारवाले चिंतित हो गए थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस समय केंद्रीय मंत्री नागपुर में ही मौजूद थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान की, बल्कि पूरे इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम भी किया। गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की जा रही है। पुलिस ने बिना समय गंवाए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। पुलिस की यह तत्परता इस बात का संकेत है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले ही उसे नाकाम किया जा सकता है। गिरफ्तार आरोपी उमेश विष्णु राउत से पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने केंद्रीय मंत्री के घर को बम से उड़ाने की धमकी क्यों दी। क्या वह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या किसी अन्य कारण से यह कदम उठाने की कोशिश कर रहा था, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि इस मामले का सही कारण सामने आ सके।

फ्लाइट में एक्स्ट्रा लगेज पर बवाल...

सेना के अधिकारी ने स्पाइसजेट के 4 कर्मचारियों को पीटा-एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा

नई दिल्ली ।

श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली. यहां एक सैन्य अधिकारी पर अतिरिक्त सामान को लेकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है. एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुए हमले में स्पाइसजेट के चार कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर भी शामिल है. एयरलाइन के अनुसार, अधिकारी, जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसने एयरलाइन कर्मचारियों को लात-घूंसों से पीटा और एक कर्मचारी पर लोहे के स्टैंड से भी हमला किया. आर्मी ऑफिसर को बताया गया था कि 7 किलोग्राम से अधिक सामान कैबिन ले जाने की अनुमति है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मी ऑफिसर कितने गुस्से में था. एयरलाइन ने बताया कि एक कर्मचारी फर्श पर बेहोश हो गया, लेकिन वह उसे लात मारता रहा. इस दौरान एक स्पाइसजेट कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा टूट गया. हवाई अड्डे की सुरक्षा का प्रबंधन करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने तुरंत आर्मी ऑफिस को रोका और स्थिति को संभाला. भारतीय सेना ने घटना का संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है और नागरिक जांच में सहयोग कर रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में हुई दोनों नेताओं की बैठक

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की वजह अभी सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। साथ ही चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा के अलावा, मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद में बहुत कम कामकाज हुआ है। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने और भारत के रूस से सैन्य उपकरण और तेल की खरीद के चलते पेनल्टी लगाने का भी एलान किया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव और बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बीच हुई मुलाकात

ओबीसी के लिए 27फीसदी आरक्षण की मांग तेज, कांग्रेस 6 अगस्त को रांची में करेगी प्रदर्शन

रांची। कांग्रेस की झारखंड इकाई राय सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 6 अगस्त को यहां राजभवन के निकट प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बीते शनिवार को दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की ओबीसी शाखा द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में निजीकरण और 'आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, ''झारखंड में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण बढ़ाकर 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (एससी) का 12 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे दबाए बैठी है। प्रदीप यादव ने कहा, ''कांग्रेस की ओबीसी शाखा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्टी का हर नेता शामिल होगा। यादव ने कहा कि झारखंड में ओबीसी आबादी लगभग 55 प्रतिशत है, जबकि देश में यह 52 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, ''ओबीसी को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संविधान में आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है।

सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल जारी, अब तक 6 खूंखार आतंकी ढेर, एक सैनिक भी घायल

जम्मू । सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल जारी है और तीसरे दिन तीन और आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही, इस अभियान में अब तक कुल छह आतंकवादी मारे जा चुके हैं। यह ऑपरेशन, जो जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे सबसे बड़े आतंकवाद रोधी अभियानों में से एक है, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति के बाद शुरू किया गया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों (जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम) के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। रात भर गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। खुफिया जानकारी के आधार पर, शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने अखल के जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था।

नए विवाद में फंसे तेजस्वी यादव, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने का लगा आरोप; चुनाव आयोग ने शुरू की जांच

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, तेजस्वी यादव पर दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है। वहीं, चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव के इस दावे को ''निराधार करार दिया कि उनका नाम बिहार की मसौदा मतदाता सूची से गायब है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि दूसरे मतदाता पहचान पत्र के पीछे की वास्तविकता को समझने के लिए जांच जारी है। यह साबित करने के लिए कि उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं था, यादव ने मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज की, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा। अधिकारियों

ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंधित हिस्से में उनका नाम क्रम संख्या 416 पर है और कहा कि यदि उन्हें अब भी कोई शिकायत है तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस बीच, आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजद नेता ने 2020 में अपना नामांकन पत्र भरने के लिए ईपीआईसी संख्या आरएबी 0456228 का इस्तेमाल किया। एक अधिकारी ने बताया, वर्ष 2015 में भी मतदाता सूची में उनका यही मतदाता पहचान पत्र नंबर दर्ज था। इस मतदाता पहचान पत्र नंबर से उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में भी मौजूद है। सूत्रों ने बताया कि आरएबी 2916120 नंबर वाला दूसरा मतदाता पहचान पत्र अस्तित्व में नहीं पाया गया है और पिछले 10 वर्षों से अधिक के रिकॉर्ड की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्ड नंबर के लिए अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। आयोग को आशंका है कि यह नंबर फर्जी या अवैध रूप से जनरेट किया गया हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, अब चुनाव आयोग द्वारा दो वोटर आईडी कार्ड की हकीकत जानने की जांच की जा रही है।

देश में बने उत्पाद खरीदने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, पीएम नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अभियान पर बोले मंत्री

नई दिल्ली । केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को देश के सभी नागरिकों से अपील की कि वे आत्म निर्भर भारत अभियान में पूरी सक्रियता से भाग लें और भारत में बने उत्पाद ही खरीदें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी के एकजुट होकर प्रयास करने से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि आत्म निर्भर भारत अभियान, एक ऐसा अभियान है, जिसमें हर भारतीय को शामिल होना चाहिए। आप जो भी सामान खरीदें, अगर आप भारत में बना सामान खरीदते हैं तो इससे आत्म निर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने हर नागरिक से अपील की है। पीयूष गोयल ने लोकसभा और राज्य सभा में साफ किया कि भारत की नीति साफ है कि भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा। शनिवार को पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल है, तब भारत को अपने आर्थिक हितों के लिए चौकन्ना रहना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों, छोटे उद्योगों का कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें उन चीजों को खरीदना चाहिए जिन्हें बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो भारत के लोगों के कौशल से बनी हैं। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो देशवासियों में इस भाव को जगाना होगा। प्रधानमंत्री ने विदेशों में शादी करके देश का धन लुटाने के बजाय भारत में ही शादी करने की सलाह दी और बताया कि कई नौजवान अब भारत में ही शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है।

ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले में बीएसई उपाध्यक्ष गिरफ्तार

ओडिशा । पुलिस ने रविवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) के उपाध्यक्ष को विशेष ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटीईटी)-2025 के पेपर लीक में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया। बीएसई को 20 जुलाई को विशेष ओटीईटी-2025 आयोजित करनी थी। इससे एक दिन पहले सोशल मीडिया पर उत्तरों के साथ एक हस्तलिखित प्रश्नपत्र वायरल होने के बाद बोर्ड ने परीक्षा स्थगित कर दी। पुलिस महानिदेशक (अपराध शाखा) विनयतोष मिश्रा ने कहा कि जांच के दौरान बीएसई के उपाध्यक्ष निहार मोहंती की लापरवाही पाई गई। उनका मुख्य आरोपी जीतन मोहराणा के साथ संदिग्ध संबंध था। मोहराणा बीएसई कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। प्रश्नपत्र लीक मामले में अब तक बीएसई उपाध्यक्ष और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

जल्द शुरू होगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, महज 2 घंटे 7 मिनट में पूरा होगा सफर- रेल मंत्री

भावनगर । भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अब जल्द ही शुरू होने वाली है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को गुजरात के भावनगर में दी। उन्होंने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी अब सिर्फ दो घंटे सात मिनट में पूरी हो सकेगी। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन की कुल लंबाई 508 किलोमीटर होगी। यह ट्रेन मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से शुरू होकर गुजरात के वापी, सूरत, आणंद, वडोदरा और अहमदाबाद तक जाएगी। इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

कई नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत

भावनगर टर्मिनस से रेल मंत्री ने वर्चुअल रूप से अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा-पुणे एक्सप्रेस और जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन सेवा जल्द शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता चाहती है कि ट्रेनों का संचालन भी जारी रहे और स्टेशनों का विकास भी हो। प्रधानमंत्री की सोच है कि दोनों कार्य एक साथ चलें और जनता को बेहतर सेवाएं मिलें।

गुजरात में कई नए रेलवे प्रोजेक्ट

रेल मंत्री ने बताया कि गुजरात में कई नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। इसमें पोरबंदर-राजकोट के बीच नई ट्रेन, राणावाव स्टेशन पर ?135 करोड़ की कोच मेंटेनेंस सुविधा, पोरबंदर शहर में रेलवे फ्लाईओवर, दो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के साथ-साथ भावनगर के नए बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल शामिल हैं।

रेलवे नेटवर्क का बड़ा विस्तार

रेल मंत्री ने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 34,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई है। अब भारत में हर दिन लगभग 12 किलोमीटर नई पटरी डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में 1,300 रेलवे स्टेशनों को नए तरीके से विकसित किया जा रहा है। विकसित देशों में जब स्टेशन बनते हैं तो ट्रेनों को बंद किया जाता है, लेकिन भारत में भीड़भाड़ को देखते हुए बिना ट्रेनों को रोके काम किया जा रहा है।

नई-नई ट्रेनें- वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत

रेल मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने कई आधुनिक ट्रेनें शुरू की हैं। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमृत भारत ट्रेनों में वंदे भारत जैसी सुविधाएं हैं लेकिन किराया कम है। अब तक आठ अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और निमूबेन बामभनिया भी मौजूद थे।